cement Directorate has come across instances where Non-Resident External (NRE) accounts have been used for illegal business in foreign exchange. As a result of the investigations conducted by the said Directorate, 158 NRE accounts involving an amount of Rs. 120 crores have been identified.

(c) and (d) These transaction are violative of the provisions of sections 8 and 9 of Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (FERA).

भारतीय शेयर बाजार में विदेशी कम्पनियां

4417. **श्री अजीत जोगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा बढ़ते हुए भारतीय शेयर बाजार को देखते हुए अपनी रिपोर्ट में क्या-क्या मुख्य टिप्पणियां की गई हैं ;

(ख) भारतीय शेयर बाजार में किन-किन देशों ने रुचि ली है ;

(ग) क्या सरकार विदेशी पूंजी निवेशकर्ताओं को कोई विशेष रियायत/सुविधा प्रदान करेगी ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान किन भारतीय कम्पनियों ने अन्तर्राष्ट्रीय शेयर बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है और इन कम्पनियों द्वारा किए गए कारोबार का ब्यौरा क्या है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा अपने पूंजी बाजार संबंधी अध्ययन में की गई प्रमुख टिप्पणियों में ये शामिल हैं—प्रतिभूतियों के लिए केन्द्रीय शोधन और निक्षेप प्रणाली की स्थापना, सभी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की निपटान अवधि में कमी, औसत बाजार भागों के बाजार मूल्यों की वृद्धि और कारोबार की वायदा प्रणाली की समाप्ति ।

(ख) विभिन्न देशों, जिनमें संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, आस्ट्रेलिया और सिंगापुर शामिल हैं, के विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय स्टाक बाजारों में निवेश करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है ।

(ग) और (घ) विदेशी संस्थागत निवेशक लाभांश और ब्याज-आय पर 20 प्रतिशत दीर्घावधिक पूंजी लाभों पर 10 प्रतिशत (जहां धारिता की अवधि एक वर्ष से अधिक हो) और अल्पावधिक पूंजी लाभों पर 30 प्रतिशत की रियायती कर दरों के पात्र हैं । पोर्टफोलियों माध्यम के अन्तर्गत कोई एक विदेशी संस्थागत निवेशक किसी कम्पनी की निर्गमित पूंजी के 5 प्रतिशत तक का निवेश कर सकता है और सभी विदेशी संस्थागत निवेशक मिलकर तथा अनिवासी भारतीय प्रत्येक कम्पनी की निर्गमित पूंजी के 24 प्रतिशत की सीमा तक निवेश कर सकते हैं । निवेश संबंधी माहौल में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया का भाग हैं ।

(ङ) निर्गमकर्ता कम्पनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 1994–95 के दौरान 31 भारतीय कम्पनियों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्टाक बाजारों में 2095.16 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के यूरो इश्यू सफलतापूर्वक जारी किए हैं । उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

उन भारतीय कंपनियों के नाम जिन्होंने 1994–95 के दौरान सफलतापूर्वक यूरो इश्यू जारी किए हैं :—

1. मैसर्स सी०ई०एस०सी०लि०
2. मसर्स ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आफ इंडिया लि०
3. मैसर्स डी०सी०डब्ल्यू० लि०
4. मैसर्स ग्रसिम इंडस्ट्रीज लि०
5. मैसर्स वल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि०
6. मैसर्स कोर पेरन्टरल्ज लि०
7. मैसर्स ई०आई०डी० पैरी लि०
8. मैसर्स रैनवैक्सी लेबोरेटरीज़ लि०
9. मैसर्स हिन्डालको इंडस्ट्रीज़ लि०
10. मैसर्स टैलको लि०
11. मैसर्स फिनोलैक्स केबल्स लि०
12. मैसर्स डा० रेड्डीज़ लेबोरेटरीज़ लि०
13. मैसर्स एस०आई०बी० इंडस्ट्रीज़ लि०
14. मैसर्स संघी पोलिएस्टर्स लि०
15. मैसर्स जे०सी०टी० लि०
16. मैसर्स सेन्चुरी टैक्सटा ,ल मिल्स लि०
17. मैसर्स एस०पी०आई०सी० लि०

18. मैसर्स इंडिया सीमेंट्स लि०
19. मैसर्स जे०के० कारपोरेशन लि०
20. मैसर्स उषा बेल्ट्रान लि०
21. मैसर्स गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लि०
22. मैसर्स श्रीराम इंडस्ट्रियल एन्टरप्राइसिज लि०
23. मैसर्स हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०
24. मैसर्स ईस्ट इंडिया होटल्स लि०
25. मैसर्स बजाज ऑटो लि०
26. मैसर्स रेमण्ड वूलन मिल्स लि०
27. मैसर्स आई०पी०सी०एल० लि०
28. मैसर्स लारसन एण्ड टूब्रो लि०
29. मैसर्स एन०ई०पी०सी०—माइकन लि०
30. मैसर्स ओरियन्टल होटल्स लि०
31. मैसर्स अशोक लीलैण्ड लि०

सरकारी कर्मचारियों पर किए जाने वाले वार्षिक व्यय में वृद्धि

4418. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों से सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों आदि पर खर्च की जा रही राशि में निरंतर वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991–92 में कुल कितनी राशि व्यय की गयी थी ;

(ग) वित्तीय वर्ष 1994–95 में कितनी राशि खर्च किए जाने का अनुमान है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि गत वर्षों में सरकार द्वारा इस राशि में निरंतर कमी करने के प्रयास किए गए है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन प्रयासों का विस्तृत ब्यौरा क्या है और भविष्य में इस राशि में कमी करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० चन्द्रशेखरमूर्ति) : (क) से (ग) मंहगाई भत्ते में वृद्धि होने, वार्षिक वेतन-वृद्धियों और मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता आदि के प्रयोजन के लिए शहरों का दर्जा बढ़ाने के कारण गत वर्षों से सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों आदि पर वार्षिक व्यय में वृद्धि हुई है । केन्द्रीय सरकारी (सिविलियन) कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर वर्ष 1991–92 के दौरान 11,462 करोड़ रु० के कुल व्यय की तुलना में 1994–95 के दौरान 15,532 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है ।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए सरकार के प्रयास जारी है । इस सम्बन्ध में सभी मंत्रालयों/विभागों को इस आशय के अनुरोध जारी किए गए हैं कि वे अपने कर्मचारियों की संख्या में कम से कम 10% की कटौती कर दें । ये आदेश भी जारी किए गए हैं कि एक साल से ज्यादा समय तक खाली पड़े हुए पदों को समाप्त हुआ समझा जाए ।

Public Sector Banks in the country

4419. SHRI T. VENKATRAM REDDY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of branches of Public Sector Banks in the country, State-wise; and

(b) the deposits growth during each of the past two years; State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) The number of branches of public sector banks including Regional Rural Bank functioning in each State as at the end of December 1994 is given in the Statement—I (*See* below)

(b) The aggregate deposit of Scheduled Commercial Banks during each of the last two years ending March, 1993 and 1994 in each State is given in the Statement-II